साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 18-24 अप्रैल 2022, वर्ष-8, अंक-3

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

कागजी कवायद से उम्मीदों पर फिरा पानी: न प्रोसेसिंग यूनिट लगीं न ही मार्केटिंग की कोई योजना बनी

'एक जिला-एक उत्पाद' की सिर्फ ब्रांडिंग

अरविंद मिश्र। भोपाल

मध्यप्रदेश के हर जिले के किसी एक बेहतर उत्पाद का चयन कर उसकी पैदावार बढ़ाने और इसे देश में पहचान दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक जिला-एक उत्पाद योजना प्रारंभ की है। तय किया था कि संबंधित उत्पाद के लिए क्लस्टर बनेंगे। उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी मदद के साथ सरकारी संस्थाएं उत्पाद की मार्केटिंग करेंगी, लेकिन कोई कारगर पहल नहीं हुई। आठ जिलों की बात की जाए तो ग्वालियर में 70 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन बैंक लोन नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस क्षेत्र से तालुक रखते हैं। बुरहानपुर में केला क्लस्टर का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लटका है। खरगोन में बाहरी कारोबारी मिर्च खरीदकर अपने नाम से बेच रहे हैं। राजगढ़ में संतरे के लिए कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं खुल पाई। अशोकनगर के टामाटर के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। इसी तरह रतलाम, मंदसौर और बड़वानी की रिपोर्ट से पता चलता है कि योजना सिर्फ ब्रांडिंग तक ही सीमित रह गई। इससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।

रतलाम: योजना में लहसुन का चयन होने के बाद 11 किसानों के लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं।

मंदसौर: एक हजार किसानों का कृषक उत्पादन संगठन तैयार हो गया है। इन्हें अच्छी किस्म की लहसुन लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बड़वानी: योजना में अदरक को शामिल किया गया है। अभी तक ग्राम हरिबड़ में अदरक की बस एक प्रोसेसिंग यूनिट मंजू गेहलोत ने शुरू की है।

- ग्वालियर में आलू की एक भी यूनिट नहीं लगी
- बुरहानपुर में केला क्लस्टर को नहीं मिली मंजूरी
- राजगढ़ के किसान संतरा बेचने बिचौलियों के भरोसे

ग्वालियर का चयनित उत्पाद आलू

ग्वालियर में एक जिला एक उत्पाद के तहत आलू और पत्थर पर काम हो रहा है। आलू को लेकर डेढ़ साल में 70 लोग आवेदन कर चुके हैं। सभी ने आलू के उत्पाद की यूनिट लगाकर चिप्स, बरी और अन्य उत्पादन की बात कही है। सहायक संचालक उद्यानिकी सुशील कौरव ने कहा कि इनमें से 15 प्रकरण बैंकों को भेजे गए थे, पर एक भी आवेदन को लोन मंजूर नहीं हुआ। दूसरी तरफ कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि पत्थर के काम को भी बढ़ावा एक जिला एक उत्पाद के तहत दिया जा रहा है।

खरगोन का चयनित उत्पाद मिर्च

खरगोन जिले में मिर्च की फसल 35 हजार हेक्टेयर में लगाई गई है। लेकिन सरकार द्वारा क्लस्टर बनाकर मिर्च की ब्रांडिंग के लिए ठोस योजना तैयार नहीं हुई। यहां की मिर्च गुंटूर, अहमदाबाद और मुंबई के कारोबारी खरीदकर अपने ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं। एक माह पहले केंद्रीय मसाल बोर्ड का दल जिले में पहुंचा था। मिर्च की फसल पर वायरस अटैक के कारण किसान बचाव में मनमाने ढंग से कीटनाशक छिड़कते हैं। दल ने मिर्च उत्पादन लागत, बाजार व खेती के तरीके पर किसानों से बात की। साथ ही कीटनाशक स्प्रे कम करने को कहा।

राजगढ़-चयनित उत्पाद संतरा

राजगढ़ जिले में 19 हजार हेक्टेयर में 12,000 किसान हर साल 38 लाख क्विंटल से ज्यादा संतरे की फसल ले रहे हैं। लेकिन इसे बढ़ावा देने जिले में प्रोसेसिंग यूनिट या कोई उद्योग नहीं खोला गया है। हालांकि अलग-अलग ब्लॉक में किसानों के छह समूह बनाए गए हैं। इनके सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर उद्यानिकी कर्मचारी किसानों को सलाह दे रहे हैं। किसान ठेकेदार अपना को फल बेच रहे हैं, फिर ठेकेदार फलों को तुड़वाकर ग्रेडिंग करने के बाद मंडियों में मुनाफा कमा रहे हैं।

अशोकनगर-चयनित उत्पाद टमाटर

अशोकनगर जिले में टमाटर की फसल को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। लेकिन इसका रकबा जिले में सिर्फ 10 से 12 हजार हेक्टेयर ही है। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने टमाटर के बजाए गेहूं या धनिया फसल को एक जिला एक उत्पाद में शामिल करने के लिए पत्र भेजा है। लेकिन इस पर आज तक उच्च स्तर से कोई निर्णय ही नहीं हो पाया है। पहले से चयनित टमाटर की फसल के लिए भी अब तक कोई काम नहीं हुआ है।

मप्र सरकार बनाएगी 'प्राकृतिक कृषि बोर्ड'

भोपाल। विशेष संवाददाता

प्राकृतिक खेती कर्मकांड नहीं, बल्कि कृषि की दशा और दिशा बदलने का अभियान है। एक जमाना था, जब रसायनिक उर्वरक की जरूरत थी। इससे उत्पादन बढ़ा, लेकिन अब दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लागत बढ़ती जा रही है। उत्पादन प्रभावित हो रहा है। मप्र जैविक खेती में अव्वल है। भूमि को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। भू-जल संरक्षण के लिए जलाभिषेक अभियान चला रहे हैं। मैं भी पांच एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करूंगा और प्रदेश में इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला में कही। वहीं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि खेतों में जिस तरह से हम यूरिया और डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, उससे आने वाले 50 साल में भूमि बंजर हो जाएगी। प्रतिवर्ष यूरिया और डीएपी की खपत बढ़ती जा रही है। इससे किसानों की लागत बढ़ने के साथ उपज की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धरती की सेहत खराब हो रही है और आमजन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

संबंधित खबर पेज 03 पर

ऐसी होगी बोर्ड की संरचना

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि बोर्ड में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अन्य मंत्री शामिल होते हैं। राज्य स्तर ब्रह्म टास्क फोर्स भी कार्य कर सकता है, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा आत्मा परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जिम्मा दिया जा सकता है। देवव्रत ने बोर्ड की संरचना का प्रारूप भी मप्र शासन को सौंपा। बोर्ड द्वारा कार्य प्रारंभ किए जाने के बाद प्रत्येक विकासखंड में किसान मित्र भी बनाए जाएंगे। बोर्ड के प्रमुख कार्यों में आत्मा से जुड़े स्टाफ को प्रशिक्षित करने, किसानों को क्षेत्र भ्रमण करवाने और प्रदर्शनी और प्रचार-प्रसार करने के कार्य शामिल हैं।

सीहोर में गेहूं बेचने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लगी कतार

सीहोर। सीहोर में गेहूं बेचने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। कतार करीब एक किलोमीटर लंबी लग रही है। भीषण गर्मी में किसान कतार में लगे परेशान हो रहे हैं। जिले में गेहूं की बंपर पैदावार हुई है। जिसके चलते गेहूं बेचने के लिए अभी से कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचने ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लग रही है। सुबह से किसान अपनी उपज ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर पहुंच रहे हैं, जिससे लंबी कतार लग रही है। धीरे-धीरे लाइन खिसकती है, जिससे किसान वाहन छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते।

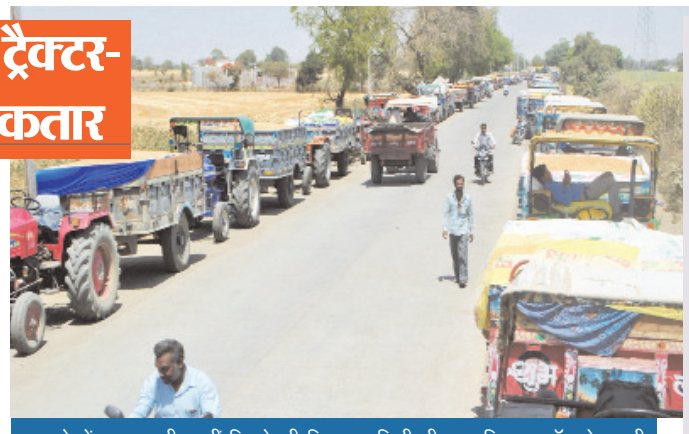

सायलो सेंटर पर रसीद नहीं मिलने की शिकायत मिली थी। यह दिक्कत सॉफ्टवेयर की वजह से आ रही है। इंजीनियर ठीक करने में लगे हैं, किसान चिंता नहीं करें।
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर सीहोर

खरीदी 16 मई तक चलेगी | खरीदी 16 मई तक चलेगी। गेहूं खरीदी सोमवार से शुक्रवार के बीच ही की जाएगी। इसके लिए किसानों को पहले से ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होंगे। बुकिंग के 3 दिन के भीतर गेहूं बेचने सेंटर पर ले जाना होगा। वे अपनी तहसील के किसी भी सेंटर पर गेहूं बेच सकेंगे। वर्तमान में मंडियों में गेहूं की कीमत 2200 रुपए क्विंटल से ज्यादा है। सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए तय किया है। ऐसे में किसान को बेहतर दाम मिलेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जम्मू-कश्मीर में करेंगे सम्मान

भोपाल और नरसिंहपुर जिपं होंगी सम्मानित

भोपाल। विशेष संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले की ग्राम पंचायत पाली में मध्यप्रदेश की भोपाल और नरसिंहपुर जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। साथ ही देश की पुरस्कृत पंचायत राज संस्थाओं को पुरस्कार की राशि खातों में अंतरित करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश की पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों की रैंकिंग के आधार पर जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा मप्र की जिला पंचायत भोपाल एवं नरसिंहपुर को 50-50 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। दोनों ही जिला पंचायतों ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं।

दीदी कैफे ने देश में मचाई धूम

जिला पंचायत भोपाल ने लगातार दो वर्षों से ग्रामीण विकास में बेहतर परिणाम दिए हैं। भोपाल ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के लिए विशेष काम किए गए और स्वच्छता में यहां की सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छ घोषित की गई हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन भी हुआ है। नल-जल योजना का संधारण महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है। महिला स्व-सहायता समूह के कार्यों में जिला पंचायत भोपाल सबसे आगे है। दीदी कैफे ने पूरे देश में धूम मचाई है। मां की बगिया की अवधारणा, जिसमें स्कूल का खुद का किचिन गार्डन होता है और बच्चों को शुद्ध आहार मिल पाता है, अत्यंत सफल है। भोपाल जिला पंचायत द्वारा प्रदेश में सबसे बेहतर काम कर सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। जिला पंचायत सभी श्रेणियों में अपने बेहतर परफार्मेंस से अव्वल बनी हुई है। जिला पंचायत भोपाल लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिये देश में पिछले 2 साल की रैंकिंग में टॉप पर रही है। जिला पंचायत ने अब देश में भी अलग पहचान बनाई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इंदौर पहुंचा मिस्र का दल

मिस्र तक जाएगा प्रदेश का गेहूं

» पसंद आया शरबती, चंदौसी लोकवन और ड्यूरम गेहूं

» बोले-जल्द एक्सपोर्टर की सूची में शामिल करेंगे भारत को

» यूक्रेन और रूस युद्ध के बाद कई देश तलाश रहे विकल्प

भोपाल। संवाददाता

मालवा के उन्नत गेहूं की रौनक जल्द ही मिस्र तक पहुंचेगी। पौष्टिकता के साथ ही कई अन्य खूबियों के चलते मध्यप्रदेश का गेहूं देशभर में बहुत लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मिस्र (इजिप्ट) का एक दल इंदौर पहुंचा। यहां उन्होंने मालवा के गेहूं निर्यातकों के साथ संवाद किया। उन्होंने खेत व भंडारण का निरीक्षण किया और विशेषज्ञों के साथ गेहूं की क्वालिटी की भी जानकारी ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, एपिडा के अधिकारियों के साथ आए दल को मालवा-निमाड़ के एक्सपोर्ट क्वालिटी गेहूं दिखाया गया। दल के प्रमुख इंजीनियर इस्लाम फरहद अब्दुल अजीज ने कहा, हमारे यहां गेहूं की आपूर्ति दूसरे देश से आयात करके ही होती है। इसका बड़ा हिस्सा हम रूस और यूक्रेन से खरीदते हैं। हम भारत से भी गेहूं खरीदना चाहते हैं। इसके लिए 2019 में भी प्रयास किए थे, लेकिन कोरोना के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। इन दिनों रूस-यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बाद हमें विकल्प देखना पड़ रहे हैं। हमारी सालाना जरूरत करीब 125 लाख टन है। मप्र के साथ ही भारत की अन्य लोकेशन पर भी जाएंगे। आशा करते हैं, भारत का नाम हमारे एक्सपोर्टर की सूची में शामिल कर सकें। दल में डॉक्टर सालेह अब्दुल सत्तार वहिंग अहमद, इंजीनियर अहमद रबी अब्दुल्ला अब्दुल कादिर भी शामिल हैं।

बीमारी मुक्त गेहूं- मध्यप्रदेश में पैदा होने वाली शरबती और मालवी (ड्यूरम) गेहूं की अलग-अलग किस्मों की खूबियों को प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही बताया कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के गेहूं में करनाल बंट नाम की बीमारी आती है, लेकिन मध्यप्रदेश का गेहूं इस बीमारी से मुक्त है।

मध्यप्रदेश में गेहूं उत्पादन

वर्ष	रकबा	उत्पादन
2018-19	77.2	252.7
2019-20	102	371.9
2020-21	98	356

(रकबा हे. और उत्पादन लाख मे.टन में)

निर्यात में 20 गुना वृद्धि होगी

निर्यातकों ने कहा कि मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। यदि वह हमें सूची में शामिल कर ले तो हमारे निर्यात में 20 गुना बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्रालय से सीबी सिंह, डॉ. रवि प्रकाश, संजय आर्य, प्रदेश से मंडी बोर्ड के डीके नागेन्द्र, सीके वशिष्ठ, महेन्द्र सिंह चौहान मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय निर्यातकों/कृषि उद्योगों को प्रदेश मे बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित करने के उद्देश्य से पात्र निर्यातकों को मंडी फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे भी गेहूं निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी।

- यहां से निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। हमने केंद्रीय दल से कहा कि यदि मप्र के एक्सपोर्टर का दल मिस्र जा कर गेहूं की जानकारी दे तो संभावनाएं और बढ़ेंगी।
  मनीष सिंह, कलेक्टर, इंदौर
- मप्र का गेहूं करनाल बंट फ्री है। एमपी ब्रांड तो दुनिया में प्रसिद्ध है। यहां प्रोटिन व हाई ग्लूटेन वेल्यू है। हमारे ड्यूरम गेहूं की मांग पास्ता के लिए बहुत है।
  केसी शर्मा, कृषि वैज्ञानिक, इंदौर
- मध्यप्रदेश का गेहूं गुणवत्ता में तो बेहतर है ही, परिवहन के लिहाज से भी यह गुजरात बंदरगाह के नजदीक है। इस कारण मालवा से गेहूं का निर्यात बहुत सुगम होगा।
  पंकज गोयल, इंदौर के प्रमुख गेहूं निर्यातक
- इजिप्ट को गेहूं निर्यात करने से पहले वहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें एपीडा मदद करेगी। आईटीसी और अन्य कंपनियों ने भी मप्र से गेहूं निर्यात की संभावनाएं हैं।
  डॉ. सीबी सिंह, क्षेत्रीय प्रभारी, एपीडा

नियंत्रण बोर्ड में हर साल संभाग के कलेक्टरों को लिखा पत्र

इंदौर में अब नरवाई जलाने पर 15 हजार रुपए तक जुर्माना

इंदौर। संवाददाता

जिले में अब खेतो में नरवाई को जलाकर नष्ट करने पर ढाई हजार से 15 हजार रुपए तक का लगेगा जुर्माना लगाया जाएगा। नरवाई जलाने से शहर में प्रदूषण के स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। कृषक गेहूं की कटाई कंबाईंड हार्वेस्टर मशीन से करा रहे हैं, जिससे फसल के अवशेष यानि नरवाई खेत में रह जाते हैं, जिसे बाद में किसानों द्वारा जलाया जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य एवं जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उप संचालक कृषि ने बताया कि नरवाई जलाने से मृदा की सतह का तापमान 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ऐसी दशा में मिट्टी में पाए जाने वाले लाभदायक जीवाणु एवं मित्र कीट आदि नष्ट हो जाते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु खेतों में डाले गए खाद एवं उर्वरक को तत्व के रूप में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं।

नया प्रावधान

पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम में 2 हजार 500 रुपए, दो एकड़ से पांच एकड़ तक पांच हजार एवं पांच एकड़ से अधिक पर नरवाई जलाने में 15 हजार का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

नरवाई न जलाने की अपील

उपसंचालक कृषि द्वारा किसानों से अपील की गई है कि फसल की कटाई के बाद फसल अवशेषों नरवाई को जलाएं नहीं, बल्कि रोटावेटर व कृषि यंत्रों के माध्यम से जुताई कर खेत में मिला दें अथवा फसल अवशेष को स्ट्रॉ रीपर चलाकर भूसा तैयार कर पशुओं को भूसा खिलाने में उपयोग करें।

भूसा 800 रुपए क्विंटल

वर्तमान में गेहूं भूसा लगभग 600 से 800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। किसान भूसा बनाकर भी अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। गौरतलब है कि नियंत्रण बोर्ड में हर साल संभाग के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर अपने जिलों में नरवाई जलाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश देता है। लेकिन किसान बड़ी संख्या में नरवाई जला देते हैं। गर्मियों में हवा तेज चलने से नार्वे के अवशेष वायुमंडल में घुल जाते हैं और स्तर बढ़ जाता है।

किसानों को फायदा, उपज का मिलेगा सही भाव

अब पांच साल तक मंडी शुल्क में मिलेगी छूट

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर सरकार का फोकस

भोपाल। मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। कृषि अधोसंरचना निधि से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगवाई जा रही हैं तो निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए मंडी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम पचास प्रतिशत के बराबर राशि या पांच साल तक छूट दी जाएगी। प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2014 से लागू है। इसमें खाद्य प्रंसस्करण के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मंडी शुल्क में छूट का प्रावधान भी है। इसके लिए मंडी अधिनियम के तहत कृषि विभाग अधिसूचना जारी करता है, जिसकी अवधि कोरोना काल में समाप्त हो गई थी। अब इसे संशोधित करके लागू किया गया है। इसमें प्रावधान किया है कि जो इकाइयां पहले से संचालित हैं, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लिए जिला स्तरीय सहायता समिति अनुशंसा करेगी और मंडी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन अंतिम निर्णय करेगा। उत्पादन प्रारंभ होने से 120 दिन के भीतर मंडी शुल्क में छूट के लिए आवेदन करना होगा।

इस व्यवस्था से खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए निवेशक प्रोत्साहित होंगे। इससे प्रसंस्करण इकाइयां व्यापारियों के माध्यम से किसानों से उपज लेंगी। इससे किसान को उपज बेचने का एक विकल्प मिल जाएगा और उचित मूल्य मिलेगा।

संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग

गेहूं खरीदी शुरू, मप्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कंगाल

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम पर पहले से 52 हजार करोड़ का कर्ज

अनाज खरीदी के लिए 34 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेगा नान

भोपाल। संवाददाता

सरकार इस समय समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज खरीद रही है। लेकिन मप्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का खजाना खाली है। ऐसे में गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीदी करने के लिए निगम ने 34 हजार करोड़ रुपए का लोन लेने की योजना बनाई है। इसके संबंध में निगम ने राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भी भेजा है जिससे बैंकों से लोन दिलाने में सरकार जमानत ले सके। गौरतलब है कि निगम पर पहले से ही 52 हजार करोड़ का कर्ज है। इसके बदले में निगम को हर महीने करीब 9 करोड़ का ब्याज चुकाना पड़ रहा है। निगम प्रतिवर्ष कर्ज के बोझ में दब रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हर साल खरीदी के लिए बैंकों से लिया जाने वाला लोन है। लेकिन वह इसे बैंकों को वापस नहीं कर पाता है। मुख्य वजह यह है कि गोदामों से समय पर गेहूं उठ नहीं पाता है जिससे निगम को केंद्र और राज्य से राशि नहीं मिल पाती।

बढ़ रहा कर्ज

केंद्र सरकार से भी प्रतिपूर्ति की राशि तभी रिलीज की जाती है जब पूरी तरह से गेहूं गोदामों से उठा लिया जाता है। पिछले 15 वर्षों के इतिहास में इस तरह से कभी नहीं हुआ की पूरी तरह से गोदामों से गेहूं उठा लिया गया हो। इससे निगम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।

ब्याज की रकम भी बैंक को नहीं मिलती

बैंकों के ब्याज की राशि भी केंद्र और राज्य सरकार निगम को नहीं देती है। इससे ब्याज मूल कर्ज में जुड़ता जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 150 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडारण है। यह 3 वर्षों से गोदामों में है गोदामों का किराया, जहां 5 माह का देना चाहिए वह 12 माह का देना पड़ रहा है। इससे निगम की माली हालत खराब हो रही है निगम इस संबंध में सरकार को कई बार पत्र लिख चुका है, लेकिन राशि की प्रतिपूर्ति और अनाज का उठाव नहीं हो रहा है।

मध्यप्रदेश और गुजराज के राज्यपाल ने किसानों से प्राकृतिक खेती का किया आह्वान, कहा

सीएम ने कहा-कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ प्राकृतिक खेती

देशी गाय प्राकृतिक खेती की खाद फेक्ट्री

» केंद्रीय मंत्री बोले- विवि में प्राकृतिक खेती को शामिल करने समिति गठित

» एमपी के कृषि पटेल ने कहा- प्रदेश को प्राकृतिक खेती वाला राज्य बनाएंगे

» भोपाल में प्राकृतिक कृषि पद्धति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

भोपाल। संवाददाता

रासायनिक खाद और कीटनाशक पर आधारित कृषि की दशा और दिशा बदलने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रकांड विद्वान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक कृषि पद्धति पर अपने विचार रखे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हुई कार्यशाला में मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सहभागिता की। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यशाला में दिल्ली से वर्चुअली सहभागिता की। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा भोपाल के प्रभारी भूपेंद्र सिंह, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्राकृतिक कृषि पद्धति पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला सिर्फ कर्म-कांड नहीं है, यह कृषि की दशा और दिशा बदलने का महायज्ञ है। वहीं गुजरात के राज्यपाल ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र की पारंपरिक कसीदाकारी से निर्मित दुशाला और स्मृति-चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। उन्होंने शिवराज को भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों में, असाधारण, गतिशील और जन-कल्याणकारी निर्णय लेने वाले प्रमुख नेता की संज्ञा भी दी।

गुजरात में डांग जिला चुना गया पायलट प्रोजेक्ट के लिए

देवव्रत ने बताया कि पूर्वी गुजरात में डांग जिले का चयन पॉयलट प्रोजेक्ट के लिए किया जाकर 19 नवंबर 2021 से प्राकृतिक कृषि के लिए व्यवस्थित कार्य प्रारंभ हुए हैं। प्राकृतिक कृषि में रुचि रखने वाले किसानों को प्रशिक्षण, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, उसके शुल्क की प्रतिपूर्ति और मार्केटिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। प्रत्येक ब्लॉक में प्रयास किए जाकर एफपीओ भी बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में प्राकृतिक कृषि बोर्ड बनाए गए हैं। मध्यप्रदेश इसी क्रम में यह बोर्ड गठित करने वाला नया राज्य होगा। देवव्रत ने बताया कि प्रत्येक ग्राम से 5 या 10 किसानों का चयन कर प्राकृतिक कृषि प्रारंभ की जानी चाहिए। इसके बाद इस कार्य का धीरे-धीरे विस्तार किया जाए।

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान प्राकृतिक खेती: राज्यपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रदेश के किसानों का आह्वान किया कि जब जागो-तभी सवेरा के भाव से प्राकृतिक खेती के लिए संकल्पित हो। वर्ष 1977 में राष्ट्रसंघ ने ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में चेताया था। इसके बावजूद ग्लोबल वार्मिंग की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रकृति ने वर्ष में चार मौसम की व्यवस्था की है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हुए मानव जाति ने एक दिन में चार मौसम कर दिए हैं। आज एक ही दिन में तेज ठंड और गर्मी दोनों हो रही है। समय रहते यदि प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य भयावह हो सकता है। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्राकृतिक खेती है। आवश्यकता है कि यह बात हर किसान तक पहुंचाई जाए। राज्यपाल ने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और जहरीले तत्वों से मानव जाति को बचाने के लिए गो-आधारित प्राकृतिक खेती ही सबसे प्रभावी समाधान है। गौ-आधारित प्राकृतिक खेती के लिए खाद और कीटनाशक देसी गाय के गोबर और मूत्र से बनते हैं। इनमें दाल का बेसन, गुड़, मुट्ठी भर मिट्टी और 200 लीटर पानी मिलाना पड़ता है।

प्राकृतिक खेती वाला राज्य बनाएंगे

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश को हम प्राकृतिक खेती वाला राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर 5-5 किमी के क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जाएगी। जनता को भोजन के लिये शुद्ध अन्न उपलब्ध कराने से अधिक पुण्य का कोई कार्य नहीं है।

किसानों ने साझा किए अनुभव

कार्यशाला के उद्घाटन-सत्र को मप्र के कृषि उत्पादन आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने संबोधित किया। कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि की पद्धति की प्रक्रिया एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्राकृतिक कृषि से उत्पन्न उत्पाद की विपणन व्यवस्था, प्रमाणीकरण एवं निर्यात की संभावना पर विषय-विशेषज्ञों के सत्रों के साथ आर्गेनिक क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं, कम्पनियों तथा प्रगतिशील कृषकों के अनुभव साझा किए गए।

प्राकृतिक खेती शून्य लागत की खेती: देवव्रत

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती के एक काम से अनेक लाभ मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से रक्षा होगी। पर्यावरण, पानी, गाय, धरती और लोगों का स्वास्थ्य बचेगा। इससे सरकार और लोगों का धन भी बचेगा। रासायनिक खेती और जैविक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती, धरती-पर्यावरण और जीवन जगत के लिए अधिक सुरक्षित है। ग्लोबल वार्मिंग भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है। केवल एक से दो फीसदी तापमान में वृद्धि से 32 प्रतिशत उत्पादन कम होगा। अतः प्राकृतिक खेती को अपनाना जरूरी है। प्राकृतिक खेती शून्य लागत वाली खेती है, जिसकी खाद की फैक्ट्री देशी गाय और दिन-रात काम करने वाला मित्र केंचुआ है। रासायनिक तत्वों का खेत में उपयोग, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देता है। जैविक खेती की उत्पादकता धीमी गति से बढ़ती है। साथ ही आवश्यक खाद के लिए गोबर की बहुत अधिक मात्रा की जरूरत होती है, जिसके लिए प्रति एकड़ बहुत अधिक पशुओं की जरूरत और अधिक श्रम लगता है।

उर्वरा क्षमता बनाए रखने हमें होना होगा सचेत: शिवराज

सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मप्र जैविक खेती में अग्रणी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रकृति का शोषण नहीं दोहन करने का विचार दिया है। यह भविष्य के खतरे को दृष्टिगत रखते हुए दिया गया मंत्र है। रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग के परिणामस्वरूप धरती का स्वास्थ्य निरंतर प्रभावित हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती मां की उर्वरा क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें सचेत रहना होगा। यह धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं, अपितु कीट-पतंगों और जीव-जंतुओं के लिए भी है। हमने कीटनाशक के अंधाधुंध उपयोग से कीट मित्रों को समाप्त कर दिया है और हमारी नदियां भी प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री की संकल्पना के अनुरूप जल-संरक्षण के लिए प्रदेश में जलाभिषेक अभियान शुरू किया गया है। हम जितना जल धरती से ले रहे हैं, उस अनुपात में हमें धरती मां को जल देना भी होगा। यह आने वाली पीढ़ी को बेहतर धरोहर सौंपने का प्रयास है। यह वास्तविकता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की जरूरत थी, उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। परंतु समय के साथ इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के अधिक उपयोग और खेती में पानी की अधिक आवश्यकता आदि से खेती की लागत बढ़ती जा रही है।

आठ राज्यों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया: तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रासायनिक खेती परिस्थिति जन्य समाधान था। आज की चुनौतियों को स्वीकार कर नवाचार की ओर बढ़ना होगा। इसी मंशा से सरकार ने प्राकृतिक खेती की पहल करते हुए मेरिस संस्था के साथ नॉलेज पार्टनरशिप कर 30 हजार किसानों के प्रशिक्षण की पहल की है। विवि शिक्षा में प्राकृतिक खेती पाठ्यक्रम को शामिल कराने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च में समिति का भी गठन किया गया है। देश के 8 राज्यों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। राज्य को प्राकृतिक खेती में नंबर वन बनाना होंगा। शिवरात किसान-गरीबों के सुरक्षा कवच हैं। कृषि के क्षेत्र में हो रहे कार्यों का ही परिणाम है कि मप्र को सात बार से निरंतर कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है।

प्राकृतिक कृषि के लिए अनुकूल मध्यप्रदेश

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि की दृष्टि से अनुकूल है। शिवराज जैसे क्षमतावान नेता मप्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अनेक क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य किए हैं। मुझे विश्वास है कि शिवराज प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश में अच्छे परिणाम लाकर दिखाएंगे। प्राकृतिक कृषि का कार्य देखने के लिए मप्र के किसान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आमंत्रित हैं। राज्यपाल देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक कृषि के प्रचार के लिए वे विभिन्न राज्यों में जाते रहते हैं। एक विशेष बात यह है कि मप्र के मुख्यमंत्री ने स्वयं मुझसे मध्यप्रदेश आने का आग्रह किया। उनके आमंत्रण पर मैंने यहां आने का कार्यक्रम बनाया। अन्य राज्यों में मुझे खुद संपर्क करना होता है। मध्यप्रदेश की ओर से मिले आमंत्रण से मैं बहुत हर्षित हुआ हूं।

प्रधानमंत्री मोदी भी लेते हैं रुचि

राज्यपाल देवव्रत ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात आ रहे हैं। वे गुजरात के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्राकृतिक कृषि के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पहले वे दिसम्बर 2021 में राष्ट्रीय कृषि और खाद्य प्र-संस्करण शिखर सम्मेलन में किसानों को प्राकृतिक कृषि के महत्व पर संबोधित कर चुके हैं। इस सम्मेलन में कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण नेटवर्क के माध्यम से किसान शामिल हुए थे। गुजरात में प्राकृतिक कृषि को लोकप्रिय बनाने के लिए यह रणनीति बनाई गई है कि कलेक्टर सहित एडीएम और एसडीएम जिले में प्राकृतिक कृषि के कार्य की मासिक रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक कृषि करने वाले ऐसे किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते हुए देशी गाय भी पाल रहे हैं।

ओझल होता दूसरों को दिशा दिखाने वाला लालटेन

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

आने वाले कुछ दशकों बाद पैदा होने वाली पीढ़ी के लिए लालटेन का नाम सुनना ऐसा लगेगा कि यह किसी नए ग्रह के प्राणी का नाम तो नहीं है या फिर कहीं सुकरात और कबीर के जमाने में पैदा हुए किसी दार्शनिक का नाम तो नहीं था। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। जनाब जरा गौर फरमाइएगा, अपने आसपास नजर दौड़ाइएगा।

कुछ हासिल हो न हो आप वर्तमान हकीकत से जरूर रूबरू हो जाएंगे। आज लालटेन रखने वाले उगंलियों पर गिनने को मिलेंगे। गांव, शहरों से लेकर महानगरों तक में आज कितनी नौजवान पीढ़ी ऐसी है जो कि लालटेन से परचित होगी। मेरा तो मानना है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में लालटेन एक दुर्लभ विलक्षण वस्तु का दर्जा हासिल जरूर कर लेगी। जिसे देश की हैरीटेज वस्तुओं की सूची में भी शामिल कर लिया जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

लालटेन महारानी संग्रालयों से लेकर प्रदर्शनियों तक में आमजन की जानकारी बढ़ाने और दर्शनार्थ प्रदर्शित की जाने लगेगी। जिसे दिखा कर नई पीढ़ी को अवगत कराया जाएगा कि कभी यह चीज भारत के गांव-कसबों से लेकर शहरों तक में प्रकाश पुंज अर्थात रात में रोशनी प्रदान करने के काम आती थी। भइये किसी जमाने में लालटेन बड़े काम की चीज रही है। यह भारत की आजादी की लड़ाई की साक्षी रही है, तो वहीं महापुरुषों से लेकर राजनेताओं तक को दिशा दे चुकी है। न जाने कितने कवियों, लेखकों ने इसकी रोशनी में ही साहित्य सृजन की नई बुलंदियों को छुआ है। वहीं कितने विद्यार्थियों और युवाओं ने इसकी ज्योति में शिक्षा ग्रहण कर के देश के उच्च पदों को सुशोभित किया है। आज बेचारी वही लालटेन अपने बजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है। हम महानगरों में रहने वाले अपने शहरों को मेट्रो शहर का दर्जा हासिल हो जाने पर जरूर गर्व महसूस करते हैं। परंतु भइये आपको बता दें दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के निवासी हमें छोटे कसबे से अधिक का भाव नहीं देते हैं।

लेकिन आज महानगरों की तो छोड़िए गांव-कसबों में भी लालटेन की बेकदरी का हाल बहुत बुरा है। मैं करीब 13 वर्ष पूर्व एक छोटे से कसबे से स्थानांतरण होकर के एक महानगर में रहने आया था। संयोग से सामान लेकर आने में लालटेन का शीशा फूट गया।

हमने महानगर में न जाने कितनी गली-कूचों से लेकर कई छोटे-बड़े बाजारों की खाक छान मारी पर लालटेन का शीशा नहीं मिला, तो नहीं मिला। न जाने कितने लोगों से पूछा कि भइये लालटेन का शीशा कहां मिलेगा, तो हम ही परिहास का विषय बन गए। क्या यार! 21वीं सदी चल रही है और आप आज भी बाबा आदम के जमाने की लालटेन के शीशा की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि लाइट बहुत जाती है, इसलिए रात में लालटेन जला लेते हैं। बढ़िया काम करती है और खर्चा भी कम होता है। अब यार...लालटेन-फालटेन को छोड़ो और इनवर्टर लगवालो। खैर हमने भी हिम्मत नहीं हारी और हमारी लालटेन के शीशे की तलाश अनवरत जारी रही। तब कहीं जाकर एक दुकान पर आर्डर देने के एक माह बाद हमें अपनी लालटेन का शीशा मिल सका। साथ ही हमें यह ज्ञान भी हो गया कि दुलर्भ वस्तुओं का मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। अब जब रात में बत्ती गुल होती है तो लालटेन महारानी धड़ल्ले से जगमगाती है। परंतु आने वाले जब देखते हैं तो लालटेन के बारे में अपने मृदु विचार प्रकट करने से नहीं चूकते हैं। इस सबको देखते हुए लगता है कि सदियों तक हम भारतवासियों को अपनी रोशनी से जगमग करने वाली लालटेन आज अपने ही देश में अपनों के बीच ही बेगानी हो गई है।

नीर के लिए पीर का स्थाई समाधान जल जीवन मिशन

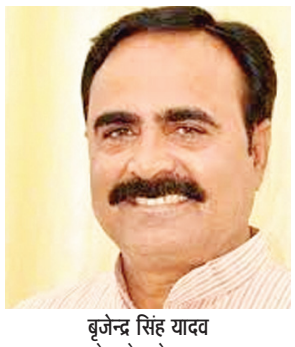

बृजेन्द्र सिंह यादव
मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य
यांत्रिकी राज्य मंत्री

लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिए दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा को अमल में लाने के लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइड-लाइन जारी की। इसके मुताबिक गांव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। मिशन में यह प्रावधान रखा गया कि ग्रामीण आबादी में नल से जल उपलब्ध कराने पर होने वाला व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन की खूबियों को जाना और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उनका मानना था कि ग्रामीण अंचल की माता-बहनों की नीर के लिए पीर को मिशन के माध्यम से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का संकल्प भी हैं कि मिशन से प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण जल की व्यवस्था समय-सीमा में हो जाए। मध्यप्रदेश का बुरहानपुर ऐसा पहला जिला है जहां मिशन के माध्यम से शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके घर में नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवा दिया गया है। जिले के दोनों विकासखण्ड में 167 ग्राम पंचायतें और 254 ग्राम हैं। इन सभी गांवों के प्रत्येक परिवार तक नल कनेक्शन से जल उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। सभी ग्रामीण परिवार मिशन से लाभान्वित होकर घर पर ही पेयजल की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मिशन में प्रावधान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में संचालित सभी आंगनवाड़ी केन्द्र और शालाओं में भी प्लेटफार्म बनाकर उनमें नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। अब आंगनवाड़ी और स्कूल के बच्चों और वहां कार्यरत शासकीय अमले को गुणवत्तापूर्ण तथा पर्याप्त पेयजल उपलब्ध रहेगा।

प्रदेश में जून 2020 से जल जीवन मिशन में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को गति मिली और ग्रामीण परिवारों को नल से जल। इस तरह गांव के हर घर में नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। अब सभी जिलों की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने के कार्य तेज गति से चल रहे हैं। प्रदेश में बदलाव के साक्ष्य के रूप में मिशन में 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन से निरन्तर जल प्रदाय शुरू हो गया है। मिशन से सभी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में भी नल कनेक्शन से पेयजल प्रदान करने के अभियान में भी तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक लगभग 69 हजार से अधिक शालाओं तथा 40 हजार से अधिक आंगनवाड़ियों में नल से जल सुलभ कराया जा चुका है। शेष स्कूल और आंगनवाड़ियों में नल से जल पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। जल जीवन मिशन में जल-संरचनाओं के निर्माण और संधारण के कार्य लगभग हर जिले में जारी हैं। ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल-प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दिए जाने का सिलसिला बना हुआ है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। विगत 22 माहों में प्रदेश के 4 हजार 143 ग्रामों के सौ फीसदी घरों में नल कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मिशन के संचालन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता समिति और गांव स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है।

योजना में निर्माण लागत की 10 प्रतिशत राशि जन-भागीदारी से जुटाने का प्रावधान है, जो श्रम, सामग्री अथवा नगद राशि के रूप में ली जा रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल ग्रामों में जन-भागीदारी का अंश 5 प्रतिशत रखा गया है। प्रदेश में मिशन के बेहतर संचालन के लिए मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार प्रमुख रूप से चार घटकों को शामिल कर उनके अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। प्रथम घटक - कार्य प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के अन्तर्गत दो टीमें गठित हैं। एक टीम तकनीकी सहायता तो, वहीं दूसरी टीम प्रबंधन समर्थन के लिए मैकेनिज्म पर काम कर रही है। जिला स्तर पर मिशन की सहायता के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनाई गई है। दूसरा घटक-कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी (आईएसए) चयनित ग्रामीण क्षेत्र में जल-प्रदाय योजनाओं से प्रभावित समुदाय को सुविधा प्रदान करने, जन-सहयोग की सहमति लेने, बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही है। प्रत्येक जिले की अपनी कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी है। तीसरा घटक-तृतीय पक्ष मूल्यांकन संस्थाएं निरीक्षण के बाद यह तय करती है कि निर्माण संस्था द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कितना कार्य कर लिया है और किए गए कार्य के विरूद्ध संस्था को कितने भुगतान की पात्रता बनती है। चौथा घटक-कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत ग्रामीण आबादी में स्थापित जल व्यवस्था का संचालन, संरक्षण और संधारण बेहतर हो सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

मिशन में ग्रामीण परिवारों को मिल रहा जल गुणवत्तापूर्ण है, इसकी समुचित जांच के लिए स्थानीय महिलाओं को एफटीके से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल-प्रदाय योजना का संचालन और संधारण बेहतर बनाए रखने के लिए वित्त प्रबंधन आवश्यक है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं के सेक्टर वाइस क्लस्टर बनाकर उन्हें जल उपभोक्ता परिवारों से जलदर प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा गया है।

संकल्पसिद्ध और कर्मसिद्ध शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के राजनैतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में कामयाब हुए हैं। यह नया अध्याय है मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 15 साल की कालावधि पूरा करना। यही नहीं, शिवराज अपने दल में भी यह गौरव हासिल करने वाले प्रदेश और देश के पहले व्यक्ति हैं। शिवराज सिंह चौहान का विकास के लिए संकल्प और लगन आम लोगों को विश्वास दिलाता है कि वे ऐसे विकास के साथ लोगों की तरक्की और खुशहाली के कामों को कर सकते हैं। उनकी मंजिल है आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश। ऐसा प्रदेश जो देश का अग्रणी प्रदेश हो जहां हर परिवार के पास रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और रोजगार हो। शिवराज सिंह चौहान के संबंध में अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वे दिन गिनने वाले लोगों में से नहीं, काम करने वालों में है। उन्होंने हमेशा काम को प्रधानता दी है और ऐसा वही कर पाता है जो पद के आने-जाने की चिन्ता से मुक्त हो। जिसका लक्ष्य पद के अनुरूप दायित्वों के निर्वहन में प्रयत्नों की पराकाष्ठा करना हो। चौहान मध्यप्रदेश में ऐसा कर पाए हैं और कर रहे हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं उनका अब तक का जीवन-क्रम बताता है कि आपातकाल के दौर में अपनी कच्ची उम्र में ही वे लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य से कारावास जा चुके हैं। गृह ग्राम जैत में मजदूरों को पूरी मजदूरी दिलाने के लिए जुलूस निकाल चुके हैं। इसके बाद अपने मातृ संगठन में विभिन्न अनुषांगिक संगठनों में विभिन्न पदों के दायित्व निर्वहन ने उन्हें अपरिमित राजनैतिक अनुभव से समृद्ध किया है। सन 1990 में थोड़े समय के लिए विधायक और फिर विदिशा से लगातार पांच बार लोकसभा चुनाव जीतकर 14 वर्ष तक की संसद सदस्यता से वे न केवल राजनैतिक रूप से परिपक्व हुए बल्कि कर्मठ जननेता और जनसेवी बन गए। यह सब कहने का आशय यह है कि वे हर रूप में, हर समय में जनसेवा और अपने दायित्वों के निर्वहन के लिये समर्पित रहे हैं। विकास और जनसेवा के साथ जनपीड़ा को हरने की उनकी प्रतिबद्धता के चलते उन्हें लगातार महत्वपूर्ण दायित्व मिलते रहे। यह अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान को मिले पद या दायित्व का निर्वहन इतनी सक्षमता से किया कि हर कसौटी उन्हें खरा उतारती रही। चाहे संगठन का काम हो या मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासन का, कोई काम उनके लिए कठिन नहीं रहा। स्वामी विवेकानंद के विचारों और कर्म से अनुप्राणित शिवराज स्वयंसिद्ध प्रमाणित होते रहे हैं। उनकी अपरिमित ऊर्जा और कुछ करने की तड़प, धारा को विपरीत दिशा में मोड़ने का माद्दा और असंभव को संभव बनाने वाली जिद का उदाहरण है उनका पन्द्रह साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल। पांव-पांव वाले भैया, जैसा उन्हें कहा जाता है, लोकसेवा और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का अविराम पथिक है। उन्हीं के शब्दों में वे जनता के पांवों में कांटे नहीं आने देंगे। खुद तो उन्हें चुनेंगे ही, लोगों को भी प्रेरित करेंगे, प्रदेश के विकास की बाधाओं रूपी कांटों को हटाने के लिए। 15 साल के मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे देश और प्रदेश में जहां एक बार पद पर पहुंचने को ही जीवन भर की उपलब्धि मानकर जश्न मनाए जाते हो, वहां चौहान की यह उपलब्धि अप्रतिम, ऐतिहासिक और उल्लेखनीय है और रहेंगी। यह उपलब्धि तब और विशिष्ट हो जाती है जब इस अरसे में उन्होंने प्रदेश के पुनर्निर्माण के कामों को उपलब्धिपरक और भूतो न भविष्यति निरंतरता और सफलता दी हो। कुल मिलाकर शिवराज के बारे में कहा जा सकता है कि सत्ता उनका कभी लक्ष्य रहा ही नहीं है। सत्ता उनके लिए अपने प्रेरणा-स्त्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों के अनुरूप अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी के दुख-दर्द दूर करने का एक साधन भर है। उनका लक्ष्य आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण का है, राजनीति को छल, फरेब, दुरभि-संधियों और जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर विकासपरक बनाने का है और इसमें वे अब तक अकल्पनीय रूप से सफल रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के अनुरूप वे राजनैतिक दल बंदी, मत-मतान्तर, धर्म-जाति, वर्ग और समुदाय से परे सबके मंगल, सबके कल्याण, सबके निरोगी होने के कार्य के कठिन व्रत को पूरा करने में जुटे हैं। उन्होंने प्रदेश में राजनीति की धारा पिछले डेढ़ दशक के अरसे में बदल दी है। अब प्रदेश में राजनीति तुष्टीकरण की नहीं विकास की ही हो सकेगी, ऐसा उन्होंने स्थापित कर दिया है। सरकार में जनता के विश्वास को और अधिक मजबूती देने के उनके प्रयास आज भी लगातार जारी हैं। वंचितों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए समर्पित शिवराज सिंह के लिए कोई भी वर्ग भूला-बिसरा नहीं रहा।

-लेखक-सुरेश गुप्ता, मप्र जनसंपर्क के अधिकारी

मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार ने दी छूट, सात लाख 43 हजार 487 किसानों ने कराया पंजीयन

किसानों से एक बार में 40 क्विंटल चना खरीदेगी सरकार

-अब तक 18 हजार 285 मीट्रिक टन हो चुकी खरीद

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में अब किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक बार में 40 क्विंटल चना खरीदा जाएगा। अभी तक यह मात्रा 25 क्विंटल निर्धारित थी। इस वजह से किसानों को दो बार मंडी आना पड़ता था। इससे समय तो बर्बाद हो ही रहा था, किसानों को आर्थिक तौर पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से उपार्जन की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। प्रदेश में पांच हजार 230 रुपए प्रति क्विंटल की दर से चना की खरीद की जा रही है। सरकार ने इस बार आठ लाख 67 हजार मीट्रिक टन चना खरीदने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चना की बोवनी हुई है।

प्राइस सपोर्ट स्कीम

प्रदेश में इस बार भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत समर्थन मूल्य पर चना खरीदा जा रहा है। सात लाख 43 हजार 487 किसानों ने पंजीयन कराया है। 21 मार्च से एक हजार 101 केंद्रों पर उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एक लाख 34 हजार 962 किसानों को उपज बेचने के लिए एसएमएस किए गए हैं। इनमें से 11 हजार 266 किसानों ने 18 हजार 285 मीट्रिक टन चना बेचा है।

पुरानी व्यवस्था लागू

अभी तक किसान एक बार में 25 क्विंटल चना ही बेच सकता था। इसकी वजह से उसे दो बार उपार्जन केंद्र आना पड़ रहा था। इससे आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। पिछले साल भी यह समस्या आई थी, तब सरकार की पहल पर केंद्र सरकार ने 40 क्विंटल चना एक बार में लेने की व्यवस्था बना दी थी, लेकिन इस बाद जब उपार्जन का काम शुरू हुआ तो फिर पुरानी व्यवस्था लागू हो गई। इसको लेकर कृषि विभाग ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था।

एक ट्राली में 40 क्विंटल चना आता है। किसान इसे लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचता है पर एक बार में 25 क्विंटल खरीदने के प्रावधान होने के कारण बाकी उपज वापस ले जानी पड़ती है। दोबारा बेचने के लिए लाने पर आने-जाने में होने वाले खर्च और मजदूरी की वजह से उसकी लागत बढ़ जाती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से मुलाकात करके एक बार में 40 क्विंटल चना बेचने की छूट देने का आग्रह किया था। इसे उन्होंने व्यावहारिक माना और आदेश जारी करवा दिए। विभाग ने सभी उपार्जन केंद्रों को विभाग ने इसकी सूचना भी दे दी है ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

3286 करोड़ रुपए से होंगे क्षतिपूर्ति वनीकरण के कार्य

पौधारोपण और गांव विस्थापन के लिए मिले 4400 करोड़ रु.

भोपाल। संवाददाता

बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम एक कदम आगे बढ़ा है। केन-बेतवा लिंक परियोजना अथारिटी ने परियोजना के लिए 4400 करोड़ रुपए राज्य सरकार के खाते में जमा करा दिए हैं। इस राशि से दोधन बांध के जलभराव क्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में आने वाले 14 गांवों के पांच हजार से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया जाएगा और पौधारोपण कर बांध के कारण उजड़ने वाले जंगल की भरपाई की जाएगी। यह राशि बांध क्षेत्र में आने वाले पेड़ पौधों का शुद्ध वर्तमान मूल्य (नेट प्रेजेंट वैल्यू) के 3500 करोड़ रुपए में से दी गई है, जो वन रोपण निधि प्रबंधन योजना अभिकरण (कैंपा) मद में जमा कराई गई है। इसके अलावा पौधारोपण, वन्यप्राणियों के लिए वैकल्पिक स्थान तैयार करने और कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान के लिए अलग से राशि दी जाएगी।

4400 करोड़ मप्र को मिले

केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में परियोजना के लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया था। इसमें से 4400 करोड़ राज्य सरकार को जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 3286 करोड़ रुपए वन विभाग को क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए दिए गए हैं। जबकि 1114 करोड़ छतरपुर जिले को दिए हैं।

किसानों को मिलेगा भरपूर पानी

परियोजना से गैर वर्षाकाल (नवंबर से मई) में मध्य प्रदेश को 1834 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 1834 अरब लीटर) और उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम (750 अरब लीटर) पानी मिलेगा। सामान्य वर्षाकाल में मध्य प्रदेश को दो हजार 350 और उत्तर प्रदेश को एक हजार 700 एमसीएम वार्षिक पानी मिल सकेगा।

- परियोजना की लागत-44 हजार 605 करोड़
- केंद्र सरकार देगी-90 प्रतिशत राशि
- राज्य सरकार देगी-5-5 फीसदी राशि
- केन बेसिन से उप्र में सिंचाई-2.27 लाख हेक्टेयर
- केन बेसिन से मप्र में सिंचाई-4.47 लाख हेक्टेयर
- बेतवा बेसिन से मप्र में सिंचाई-2.06 लाख हेक्टेयर
- मध्य प्रदेश के हिस्से में जाएगी-बिजली

किस जिले में कितने हेक्टेयर में सिंचाई

जिला	सिंचाई रकबा (हेक्टेयर में)
पन्ना	70 हजार
छतरपुर	3,11,151
दमोह	20,101
टीकमगढ़	50,112
सागर	90 हजार
दतिया	14 हजार
विदिशा	20 हजार
रायसेन	06 हजार

बैठकों का दौर शुरू

राशि से कलेक्टर जलभराव क्षेत्र में निवासरत परिवारों को दूसरे स्थानों पर विस्थापित करेंगे। इसके साथ ही परियोजना निर्माण को लेकर बैठकों को दौर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्से के बुंदेलखंड को पीने एवं सिंचाई का पानी देने के लिए केंद्र सरकार ने परियोजना को मंजूरी दी है। पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच फरवरी 2022 में अनुबंध हुआ है।

रखवाली के लिए देने पड़ रहे दो गुना पैसे

खंडवा में 200 रुपए किलो बिक रहे नींबू

-जिले में आम लोगों की पहुंच से हुए बाहर

खंडवा। संवाददाता

बाजार में नींबू महंगे बिकने से आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। वहीं नींबू का बगीचा लगाने वाले किसानों को इनकी सुरक्षा महंगी पड़ रही है।

जिले में पुनासा और पंधाना विकासखंड में करीब 50 हेक्टयर में नींबू की खेती होती है। नींबू चोरी होने के डर से बगीचों और खेतों की चौकीदारी के लिए डेढ़ गुना ज्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है। तहसील मुख्यालय पुनासा के किसान भारत सिंह पटेल के तीन एकड़ बगीचे में नींबू के तीन सौ से अधिक पेड़ लगे हैं। इनमे से अधिकांश पेड़ों पर नींबू लगे हैं। बगीचा मुख्य मार्ग और गांव पास होने से नींबू की चौकीदारी करनी पड़ रही है।

24 घंटे पहरेदारी

24 घंटे चौकीदार के लिए मजदूरी भी ज्यादा लग रही है। आम मजदूर जहां 300 रुपए में मिल जाते हैं। वही नींबू की चौकीदारी के लिए चार से पांच सौ रुपए मजदूरी देनी पड़ रही है। किसान भारत सिंह स्वयं उम्रदराज होने के बाद भी बगीचे में नींबू की चौकीदारी व देखभाल के लिए जाना पड़ रहा है।

किसान को दो गुना आय की उम्मीद

नींबू महंगा होने के कारण इस बार लगभग दो गुना आय होने की उम्मीद है। नींबू का बगीचा लगाने वाले ग्राम भिलाई के किसान कालू मालवीय और सोनू सलूजा भी नींबू की रखवाली में व्यस्त हैं। इनके बगीचे में करीब 40 पेड़ लगे हैं। इनकी रखवाली दिन रात करनी पड़ रही है। ऐसा पहला मौका आया है जब नींबू के भाव में भारी तेजी आई है।

इसलिए महंगे हो गए नींबू

जिला उद्यानिकी अधिकारी राजू बड़गाया ने बताइस की नींबू की फसल साल में दो बार होती है। गर्मी की तुलना में ठंड के समय उत्पादन अधिक होता है। इस वर्ष बेमौसम बारिश की वजह से अधिकांश प्रदेशों में नींबू की फसल प्रभावित हुई है। इसलिए नींबू के भाव में तेजी आ गई है। नींबू के दाम सामान्य होने में अभी समय लगेगा।

शिवपुरी,श्योपुर, भिंड, मुरैना और दतिया के किसान चिंतित, अंचल के किसानों को 18 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान

ग्वालियर जिले में 2000 हजार बीघा की फसल राख

चंबल के छह जिलों में 2250 बीघा की फसल जलकर खाक

खेमराज मौर्य। शिवपुरी

भीषण गर्मी से तप रहे ग्वालियर-चंबल के किसानों की उम्मीदें जलकर खाक हो रही हैं। पिछले तीन ग्वालियर के भितरवार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया में कई स्थानों पर अलग-अलग कारणों से खेतों में कटने को तैयार खड़ी साढ़े चार हजार बीघा फसल जल गई। इससे किसानों को 18 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। किसानों की मानें तो ग्वालियर जिले में करीब 2000 हजार बीघा में तो अन्य चार जिलों में 2250 बीघा की फसल को नुकसान हुआ है। भितरवार में हुई अग्निकांड की घटना के बाद प्रशासन ने प्राथमिक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। प्रशासन के अनुसार 1300 बीघा में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। जिसमें 199 किसान प्रभावित हुए हैं। इन सभी के खातों में 70 लाख रुपए की राशि पहुंचा दी जाएगी। वहीं मुरैना, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी में अब तक 2250 बीघा से ज्यादा खेतों की फसल जलकर खाक हो चुकी है। इससे किसानों को 9 करोड़ 40 लाख का नुकसान का अनुमान है।

बीड़ी से सुलगीं किसानों की उम्मीदें

मुरैना जिले के रिठौरा क्षेत्र में आग से 800 बीघा गेहूं की पकी हुई फसल जलकर राख हो गई। कुछ ग्रामीणों का कहना है, कि फसल काट रहे किसी मजदूर ने सुलगती बीड़ी फेंकी, जिससे सूखी फसल में आग बेकाबू हो गई। वहीं कुछ किसानों का कहना है, भिंड जिले के कंचनपुर गांव में फसल काट रही हार्वेस्टर मशीन का एक हिस्सा चलते समय पत्थर से टकरा गया, जिससे उठी चिंगारी से खेतों में आग भड़क गई थी। इसी तरह भिंड जिले में 800 बीघा से ज्यादा की फसल जलकर खाक हो चुकी है।

लापरवाही से लग रही आग

शिवपुरी और श्योपुर जिले में भी 300 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर स्वाहा हो चुकी है। आगजनी के अधिकांश हादसे बिजली तारों में फाल्ट होने, खेतों में बीड़ी फेंकने जैसी लापरवाही से हो रही हैं। गेहूं की पकी हुई फसल, हल्की सी चिंगारी से भीषण आग पकड़ लेती है। इसीलिए इस सीजन में ग्रामीण खासकर खेतों के ऊपर से निकली बिजली लाइनों से बिजली सप्लाई बंद रखने के निर्देश होते हैं, पर इनका पालन नहीं हो रहा। आगजनी की कई घटनाएं बिजली लाइनों में फाल्ट के कारण हुई हैं।

एक नजर में किसानों का नुकसान

आगजनी से मुरैना, भिंड, श्योपुर और शिवपुरी जिले में 2250 बीघा खेतों की फसल जली है। इससे किसानों को हुए 9.40 करोड़ रुपए के नुकसान के हिसाब को इस तरह समझिए, कि 2250 बीघा जमीन में 8 क्विंटल के हिसाब से 18000 क्विंटल गेहूं की पैदावार होती। गेहूं का भाव 2150 से 2200 रुपए क्विंटल है। इस हिसाब से 3.90 करोड़ के गेहूं की उपज का नुकसान हुआ है। गेहूं के साथ इसी फसल से 27000 क्विंटल से ज्यादा भूसा पैदा होता। भूसे का भाव 2000 रुपए क्विंटल तक है, इसीलिए आग से 5.40 करोड़ से ज्यादा कीमत का भूसा भी जलकर नष्ट हो गया है।

नरवाई में आग न लगाएं

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि मध्यप्रदेश के विभिन्न हिस्सों से खेतों में आग लगने की कुछ खबरें मिल रही हैं। किसान भाइयों से अपील है कि आप सभी जरूरी सावधानी रखें। नरवाई में आग न लगाएं, विशेष रूप से जब खेत के आस-पास फसल हो। रीपर का इस्तेमाल तभी करें जब आस-पास की भी फसल कट चुकी हो। धूम्रपान बिल्कुल न करें।

सिंधिया और तोमर किसानों से मिले

अंचल में किसानों की फसल जलने की घटनाओं के बाद राजनेता भी खेतों तक पहुंच रहे हैं। मुरैना दौरे पर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जब पता चला कि अंबाह के रिठौरा क्षेत्र में आगजनी की घटना हुई तो वे सभी कार्यक्रम छोड़कर सिलगिला गांव पहुंच गए। वहीं ग्वालियर प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भितरवार क्षेत्र के किसानों के आंसू पोंछने के लिए पहुंचे थे।

भितरवार पहुंचे पूर्व सीएम नाथ-दिग्गी

भदेश्वर घरसोंधी सहित कई गांवों में किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख होने पर जायजा लेने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, विधायक सुरेश राजे, लाखन सिंह आदि के साथ पहुंचे और पीड़ित किसानों से मिले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री आते हैं और सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रत्येक किसान को मुआवजा मिलना चाहिए।

प्रभारी मंत्री सिलावट बोले, किसानों की सूची बनाओ

भितरवार क्षेत्र के अग्निपीड़ित किसानों से मिलने जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भितरवार एडीएम अश्विनी रावत से कहा कि किसानों की सूची बनाओ और खातों में पैसा पहुंच जाना चाहिए। प्रभारी मंत्री ने किसानों से बात की और भरोसा दिलाया कि भाजपा किसानों के साथ है और सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर नईदिल्ली तक पूरी चिंता की जा रही है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास एक से पांच बीघा तक जमीन है उनकी अलग सूची बनाई जाए और तत्काल मदद की राशि ट्रांसफर की जाए। राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। 245 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई है। 199 प्रभावित किसानों की सूची बनाई गई है।

राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा-फसल नुकसान की भरपाई करेगी सरकार

इधर, मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में आगजनी से फसलों को हो रहे नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए सर्वे होगा, जिस किसान की फसल को नुकसान होना प्रमाणित होगा, उसे राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रविधानों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को निर्देश दिए हैं कि वे सभी कलेक्टरों से कहें, किसानों को राहत पहुंचाने में तत्परता दिखाएं। भोपाल, विदिशा, सागर, ग्वालियर, चंबल, शिवपुरी, रीवा, सीधी, सहित अन्य जिलों में आग लगने से खेत में फसल नष्ट होने की घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में किसानों को मुआवजे के लिए भटकना न पड़े, इसके मद्देनजर प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और सर्वे कर प्रकरण बनाएंगे। नुकसान के आधार पर तय होगा कितना मुआवजा मिलेगा।

आदिवासियों के लिए महुआ फूल आमदनी का सहारा, लजीज व्यंजन, शराब और औषधी में भी उपयोग

सीधी में महुआ का रिकॉर्ड उत्पादन

सीधी। संवाददाता

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सीधी जिले में महुआ फूल और उसका फल यहां के आदिवासियों का जीवन माना जाता है। जिले भर के आदिवासियों का महुआ फूल से गहरा संबंध है। शराब बनाने के साथ ही महुआ फूलों का उपयोग विविध व्यंजनों को बनाने में भी किया जाता है। आदिवासियों की महुआ फूल से आर्थिक आमदनी भी होती है। औसतन 36 से 70 रुपए किलो महुआ फूल बेचा जाता है। महुआ फूल से निर्मित शराब भी 150 रुपए प्रति बोतल बिकती है। सूखे महुआ को लंबे समय तक उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सकता है। त्यौहार के अवसर पर लजीज व्यंजन बनाने में भी महुआ के मीठे फूलों का उपयोग होता है। महुआ फूल में चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होने से इसका औषधीय उपयोग भी है। हड्डियों के रोगों के लिए दवा तैयार करने में महुआ फूल का उपयोग किया जाता है। सीधी जिले में महुआ का भारी उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। वन क्षेत्रों में तो महुआ का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।

दक्षिणी भाग में भारी उत्पादन

सीधी जिले में महुआ उत्पादन को लेकर आदिवासी बाहुल्य कुसमी विकासखंड और उससे लगा मझौली विकासखंड काफी अग्रणी है। ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ के पेड़ों से फूल गिरने पर बीनने में काफी प्राथमिकता दिखाई जाती है। सीधी जिले में मार्च महीने के आरंभ से ही महुआ फूल गिरना शुरू हो जाता है।

आमदनी का अतिरिक्त जरिया महुआ

महुए के फूल से न केवल आदिवासी परिवार अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके लिए यह अतिरिक्त आय का जरिया भी बन गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी परिवार ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी महुए के फूल से अतिरिक्त आमदनी कर रहे हैं। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष महुए के फूल अच्छे हैं। जिसके चलते ग्रामीणों को बेहतर आमदनी की उम्मीद बनी हुई है। इस वर्ष जंगलों और खेतों में महुए के फूल बड़ी संख्या में गिर रहे हैं।

आबकारी विभाग का प्रत्यक्ष रूप से महुआ से कोई लेना-देना नहीं है। ये अवश्य है कि जिले के आदिवासी बाहुल्य कुछ अधिसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों को सीमित मात्रा में स्वयं के उपयोग के लिए महुआ शराब बनाने की छूट मिली हुई है। वहीं कुछ लोग महुआ से अवैध शराब भी बनाते हैं जिस पर कार्रवाई होती है।

डॉ. अंशुमान सिंह चडार,
जिला आबकारी अधिकारी, सीधी

सीधी जिले में इस वर्ष मौसम की अनुकूलता के चलते महुआ फूल का उत्पादन पिछले वर्ष से तीन गुना ज्यादा है। इस वर्ष महुआ फूल के बंफर उत्पादन के चलते दाम गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। इस वजह से अभी तक कोई भी स्टाकिस्ट महुआ फूल की खरीदी के लिए आगे नहीं आए हैं। वर्तमान में 36 सौ रुपए क्विंटल महुआ फूल के दाम हैं। दाम और भी बढ़ सकते हैं।

कमल कामदार,
स्टाकिस्ट, महुआ फूल

सेहत पर भारी नियमः गर्मी में परोसा जा रहा ज्वार-बाजरा

प्रदेश के 24 जिलों में स्टाक निपटाने बंट रहा मोटा अनाज

प्राथमिक परिवार

अभी प्राथमिक परिवार को गेहूं दो किलो, मोटा अनाज दो किलो और चावल एक किलो दिया जा रहा है। हालांकि यह राशन प्रति सदस्य प्रति माह है।

अंत्योदय परिवार

अंत्योदय परिवार को गेहूं 20 किलो, मोटा अनाज 10 किलो और चावल 5 किलो वितरित किया जा रहा है। यह प्रति परिवार प्रतिमाह है।

भोपाल। संवाददाता

अप्रैल की तेज गर्मी में सरकार राशन की दुकानों पर मोटा अनाज (ज्वार-बाजरा) बांट रही है। पारा 43 डिग्री के पार है और सर्दियों में खाए जाने वाला मोटा अनाज जबरिया राशन की दुकानों पर भिजवा दिया गया है।

प्रदेश में अप्रैल माह के मोटे अनाज का कोटा आवंटित होकर दुकानों पर बंटना भी शुरू हो गया है। राशन की दुकानों पर लोग ज्वार बाजरा लेने से मना भी कर रहे हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि आवंटन आया है तो लेना पड़ेगा। प्रति सदस्य दो किलो मोटा अनाज बांटा जा रहा है। प्रदेश में 24 जिलों मे मोटा अनाज का वितरण कराया जा रहा है। सर्दियों में खरीद हुई, लेकिन मार्च तक भी सरकार बंटवा नहीं पाई। गौरतलब है कि राशन वितरण में दिए जाने वाले अनाज में गेंहू, मोटा अनाज और चावल दिया जा रहा है। जिन जिलों में मोटे अनाज का स्टाक है और इसके क्लियर करने के लिए राशन सामग्री में इसे जोड़ दिया गया।

15 मार्च के बाद से ही प्रदेश में गर्मी बढ़ना शुरू हो गई और अब सीवियर हीट वेव की स्थित तक आ चुकी है। ऐसी गर्मी में मोटा अनाज खाया नहीं जा सकता है क्योंकि यह सर्दियों में खानपान में शामिल किया जाता है।

चार माह में क्यों नहीं बांटा

मोटे अनाज की खरीद अक्टूबर-नवंबर के माह में की जाती है और इस बार भी की गई थी। खरीद करने के बाद नवंबर,दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन महीनों में भी वितरण नहीं कराया जा सका। अब गोदामों में स्टाक क्लियर करने के लिए राशन की दुकानों की सामग्री में जोड़ दिया गया। इतनी गर्मी में मोटा अनाज कैसे लोग खाएंगे यह देखने वाला कोई नहीं है।

समर्थन मूल्य 2015 रुपए पर गेहूं की खरीदी

भोपाल उपार्जन केंद्रों पर गड़बड़ाई व्यवस्था

भोपाल। संवाददाता

जिले में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरदीने के लिए 77 उपार्जन केंद्र बनवाए गए हैं। इन दिनों केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहां पर जो व्यवस्थाएं करवाई गई है वह अधिक संख्या होने की वजह से अब गड़बड़ाने लगी हैं। ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जिले में उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्य 2015 रुपए पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। मंडी और समर्थन मूल्य का भाव लगभग एक समान होने की वजह से अब केंद्र के पास स्थित गांव के किसान केंद्रों पर ही गेहूं ले जा रहे हैं। हर दिन हजारों क्विंटल गेहूं केंद्रों पर पहुंच रहा है। यहां तोल के लिए कुल आठ कांटे रखे हुए हैं। अब यह कांटे भी गेहूं की आवक के हिसाब से कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में किसानों द्वारा लाया गया गेहूं समय पर नहीं

तुलने की वजह से उन्हें केंद्र पर एक से दो दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र पर छाया के लिए जो टेंट लगवाए गए हैं वे अब छोटे पड़ने लगे हैं। बढ़ती संख्या की वजह से यहां पर अधिक से अधिक किसानों को धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। इधर पानी के लिए भी कुछ ही मटके रखे हैं जो गर्मी के मौसम में किसानों की बढ़ती संख्या के हिसाब से कम पड़ रहे हैं। इधर कर्मचारियों की भी कमी खल रही है इस वजह से भी किसानों को गेहूं तुलवाने में समय लग रहा है। हालांकि गेहूं खरीदी 16 मई तक की जाएगी।

-सिर्फ 181 नंबर को डायल करने से सामने आ जाएगा जमीन का रिकॉर्ड

मोबाइल पर मिलेगी जमीनों की 'कुंडली'

» मोबाइल पर मिलेगी खसरा-खतोनी की नकल, 10 रुपए देना होगा शुल्क

भोपाल। संवाददाता

अब किसानों को उनके मोबाइल पर खसरा-खतौनी सहित अन्य राजस्व रिकॉर्ड की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उन्हें सीएम जनसेवा 181 पर मोबाइल से फोन कर दस्तावेज की मांग करनी होगी। इसके लिए दस रुपए के हिसाब से प्रति कॉपी शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इस कॉपी का उतना ही महत्व होगा जितना कि तहसील से निकलवाए गए राजस्व रिकॉर्ड सत्यापित

कापी का होता है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने यह काम भोपाल ई-गवर्नेंस लिमिटेड को दिया है। आईटी सेंटर और लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए जन सेवा केन्द्र और एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटरों को सेवा प्रदाता के लिए अधिकृत किया है।

हार्ड कॉपी लेने जाना होगा जनसेवा केंद्र

लोगों को 181 पर फोन कर बताना होगा कि उन्हें फलां खसरा नम्बर की कॉपी चाहिए या बी-1 की नकल चाहिए। ऑनलाइन भुगतान के संबंध में दस्तावेज की जानकारी भी देनी होगी। नक्शे की भी नकल उपलब्ध कराई जाएगी। सारी जानकारी देने के बाद किसान को मोबाइल पर जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। हार्ड कॉपी निकलवाने किसानों को एमपी ऑनलाइन या जनसेवा केंद्र जाना होगा।

सॉफ्ट कॉपी में भी हो जाएगा काम

हालांकि सॉफ्ट कॉपी भी वे दिखाकर अपना काम कर सकेंगे। बताया जाता है कि जिला और संभाग स्तर पर राजस्व से जुड़ी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिले के आईटी अधिकारियों को अधिकृत किया है, जो एमपी ऑनलाइन और जनसेवा केन्द्रों को एक हफ्ते के अंदर ये रिकॉर्ड इन सेंटर्स को उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

2014 से 2019 तक दो हजार 638 प्रोजेक्ट बने, उदासीनता के कारण एक हजार 933 ही हो पाए पूरे

प्रदेश में ठप हो गई सांसद आदर्श ग्राम योजना

दो साल में मात्र 12 सांसदों ने पंचायतें ली गोद

भोपाल। संवाददाता

केंद्र सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए आदर्श ग्राम विकसित करने की योजना बनाई थी। मकसद यही था कि आदर्श ग्राम में सभी तरह की सुविधाएं हों और अन्य ग्राम पंचायतें उन्हें देखकर प्रेरित हो सकें। जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसकी जिम्मेदारी सांसदों को सौंपी गई थी। शुरुआती दौर में मध्य प्रदेश में बेहतर काम हुआ। अधिकांश सांसदों ने पंचायतों को चयन किया। ग्राम विकास योजना भी बनी और कार्य भी स्वीकृत हुए, लेकिन कोरोना काल में योजना ठप सी हो गई। 2019 से 2021 के अंत तक एक हजार 394 प्रोजेक्ट ही स्वीकृत हुए। इनमें भी 287 ही पूरे हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दो साल कार्य की गति प्रभावित हुई है। सड़कों को रौंदते और मुरमकी धूल उड़ाते डंपरों से परेशान ग्रामीणों ने सोचा था कि आदर्श ग्राम होने के बाद उनके गांव को इस समस्या से निजात मिलेगी। कुछ बेहतर होगा, लेकिन डंपरों से मुक्ति मिलने के बजाय हाल ही में गांव में शराब की नई दुकान की अनचाही सौगात मिल गई। यह स्थिति दो साल पहले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा गोद लिए तिल्लौर खुर्द गांव की है।

इंदौर की स्वच्छता दिखावा

इंदौर शहर की तरह तिल्लौर खुर्द में भी स्वच्छता के लिए कचरा इकट्ठा किया जाने लगा है, लेकिन यह स्वच्छता केवल दिखावा भर है। कचरा इकट्ठा करके गांव के बाहर एक जगह डाला जा रहा है, जो उड़कर खेतों में जा रहा है। गीले और सूखे कचरे को छांटने के लिए सेग्रिगेशन शेड बनाया गया है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। गांव में पानी की टंकी बन गई है जिससे घरों में नल का पानी आने लगा है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि योजना के अनुसार ही विकास के कार्य हो रहे हैं। शराब दुकानें के मामले में अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।

ताई के गोद लिए गांव को भूले अफसर

पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन ने सांवेर क्षेत्र के पोटलोद गांव को जब गोद लिया था, तो प्रशासनिक मशीनरी गांव के विकास में जुट गई थी। नए-नए प्रोजेक्ट तैयार किए गए। गांव की मुख्य सड़क बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन ताई का कार्यकाल खत्म होते ही पोटलोद गांव को अफसर भूल गए। जलसंकट की समस्या अभी भी दूर नहीं हो पाई है।

भोपाल सांसद के भी हाल बेहाल

भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने योजना के तहत बंगरसिया गांव को गोद लिया था। वर्ष 2019 से 2022 तक ग्राम पंचायत में 27 लाख 49 हजार के कार्य करवाए जा चुके हैं। 34 लाख 80 हजार के स्वीकृत कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। पूर्व सांसद आलोक संजर ने तारासेवनियां गांव को गोद लिया था। यहां 57 लाख 47 हजार के नाली निर्माण से लेकर अन्य कार्य कराए गए लेकिन अब स्थिति फिर बिगड़ने लगी है।

कोरोना काल में रुक गई थी सांसद निधि

राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी का कहना है कि करेली जनपद में स्कूल में पानी, बाउंड्रीवाल, शमशान घाट का विस्तार सहित अन्य कार्य करवाए गए हैं। कोरोना काल में सांसद निधि नहीं मिली, इसका असर कामों पर पड़ा है, लेकिन अब यह फिर प्रारंभ हो गई है। अब नया गांव गोद लेकर जल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा।

यह सही है कि कोरोना काल में विकास और प्रगति धीमी हुई है किंतु प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुनः प्रदेश में विकास कार्य गति पकड़ चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए मप्र को आत्म निर्भर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करके धरातल पर उतारा जाएगा। कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। सभी संसद सदस्यों से आग्रह करेंगे कि वे योजना में पंचायतों का चयन करें।

महेंद्र सिंह सिसौदिया,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री

रोजाना 400 क्विंटल बिकने आ रहा नर्मदांचल में तरबूज की बंपर पैदावार

नर्मदापुरम। संवाददाता

नर्मदांचल की उर्वरा माटी में खाद्यान्न और सब्जी के बाद तरबूज की फसल भी बंपर हो रही है। क्षेत्र के खेतों में लगे तरबूजों से पिकअप भराकर आ रही है, जिसकी नीलामी सुबह कृषि उपज मंडी के सब्जी मंडी वाले क्षेत्र में हो रही है।

आने वाले दिनों में और ज्यादा मात्रा में तरबूज आने की संभावना बन रही है। इससे किसानों की स्थिति भी मजबूत हो रही है। दरअसल, नर्मदांचल में अब परंपरागत खेती से हटकर फलों के उत्पादन की ओर भी किसानों का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले नर्मदा और तवा के तरबूज, खरबूज, ककड़ी बड़ी मात्रा में आते थे। लेकिन अब डंगरबाड़ियों में फलों की जगह सब्जियों ने ली है। सब्जी की पैदावार भी हजारों क्विंटलों में हो रही है।

खेतों में तरबूज की खेती

नर्मदा और तवा की रेत की बजाए खेतों में तरबूज की खेती हो रही है। इससे तरबूज की पैदावार तेजी से बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजार में इसकी मांग भी खासी बढ़ गई है। पिछले कुछ दिन से मंडी में लगातार तरबूज की खेप आ रही है। पिकअप में छोटे व्यापारी या किसान

व्यापारियों को मुनाफा

किसान तरबूज की खेती करते हैं जो थोक में किसी व्यापारी को दे देते हैं। अनेक व्यापारी खेत में ही पिकअप लेकर पहुंच जाते हैं। किसान से कम दाम में लेकर व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इन व्यापारियों द्वारा सुबह खरीदी के बाद विभिन्न शहरों में तरबूजों की खेप पहुंचाई जा रही है।

कम समय की फसल

किसानों एवं उद्यान केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि तरबूज की फसल कम समय में ही तैयार हो जाती है। इससे किसान इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले डंगरबाड़ियों में इसकी सीमित पैदावार होती था।

दर्जन भर गांवों में खेती

जिले में तरबूज की फसल तेजी से आ रही है। जिनमें से सोहागपुर, माखननगर के साथ ही नर्मदापुरम ब्लाक के रायपुर, डोंगरबाड़ा, जासलपुर,जासलपुर टील, घानाबड़, बांद्राभान, सांगाखेड़ा, शुक्करवाड़ा फार्म,बालाभेंट, रोहना, सहित अनेक गांवों में तरबूज की खेती हो रही है। अब तेजी से किसानों का रुझान तरबूज की तरफ बढ़ रहा है। यही नहीं, तरबूज से सभी को फायदा हो रहा है। चाहे किसान,थोक व्यापारी या फुटकर में बेचने वाले दुकानदार सभी को लाभ मिलता है। खरीददार को भी कम पैसे में मौसमी फल मिल जाता है।

क्षेत्र में तरबूज की खेती करने की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है। यह नकद फसल है। कम दिनों में ही तैयार होकर फल देने लगती है। किसानों को भी अच्छा फायदा हो जाता है।

रीता उइके, उप संचालक, उद्यानिकी

ढाई घंटे में लाखों की बिक्री

मंडी में अनाज,सब्जी के बाद तरबूज के वाहनों के खड़े होने के लिए पर्याप्त जगह है। बेचने और खरीदने वाले सुबह 9 बजे से मंडी में पहुंच जाते हैं। दो से ढाई घंटे में लाखों रुपए के तरबूजों की थोक में बिक्री हो जाती है। उसके बाद जो खरीदते हैं वे अपनी दुकानें बाजार में खुले स्थान पर ढेर लगाकर 20 रुपए किलो में बेच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक औसतन 300 से 400 क्विंटल तरबूज की बिक्री एक दिन में हो रही है। शहर में ही प्रतिदिन साढ़े चार सौ क्विंटल तरबूज की आवक हो रही है। इसके बाद यहां से आसपास के जिले में तरबूज की खेप पहुंच रही है।

कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री का माना आभार

भोपाल। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में उपार्जन केंद्रों पर चना फसल की प्रतिदिन प्रति किसान उपार्जन सीमा मात्र 25 क्विंटल थी। किसान अपनी ट्राली में 40 क्विंटल चना लेकर आता था किंतु 25 क्विंटल की सीमा होने के कारण किसानों को 15 क्विंटल चना वापस ले जाना पड़ता था। तोमर ने दिल्ली में हुई चर्चा में किए गये अनुरोध पर किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करने के निर्देश दिए थे। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि अब किसान प्रतिदिन उपार्जन केन्द्र पर 40 क्विंटल चना लेकर आ सकते हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)